विचार बिन्दु

अपनी नम्रता का गर्व करने से अधिक निंदनीय और कुछ नहीं है। –मारकस

जनमानस में रियासती उपाधियों की पुनर्स्थापना: अतिरंजित और अंतर्विरोधों से भरा विमर्श

जनमानस में रियासती उपाधियों की पुनर्स्थापना – यह शीर्षक अपने आप में ही विरोधाभासों से भरा हुआ है। आखिर इस कथित प्रयास के पीछे कौन है? निश्चय ही कोई लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकार तो नहीं। और यह भी विचित्र है कि 'जनमानस' को इतना भोला और मूर्ख क्यों दिखाया जा रहा है? आज़ादी के सात दशक बाद क्या सचमुच यह मान लिया जाए कि जनता को इतनी आसानी से बहकाया या ब्रेनवॉश किया जा सकता है कि वह पुराने राजसी प्रतीकों को स्वीकार कर ले, जबकि लोकतांत्रिक मूल्य समाज के हर वर्ग में गहराई से जड़ें जमा चुके हैं? क्या जनता को इतना भी श्रेय नहीं दिया जाना चाहिए कि वह स्वयं समझदार है, बजाय इसके कि उसे बिना विवेक और स्वतंत्र चिंतन वाले बच्चों की तरह पेश किया जाए?

लेखक अपने लेख की शुरुआत संविधान का हवाला देकर करते हैं समानता, समान अधिकार और यह सिद्धांत कि कोई भी किसी से ऊपर नहीं है। ठीक है, यह बात स्वीकार्य और निर्विवाद है। लेकिन इसके बाद वे चतुराई से प्रजामंडल आंदोलन को सामने ले आते हैं और उसे जनसाधारण द्वारा लड़ा गया एक दीर्घ संघर्ष बताने लगते हैं। यहीं समस्या शुरू होती है। इतिहास की सामान्य समझ रखने वाला कोई भी व्यक्ति जानता है कि प्रजामंडल आंदोलन कुछ गिने–चुने अभिजात, संपन्न और उच्चवर्णीय सवर्णों द्वारा संचालित था, जो स्वयं मौजूदा सत्ता में भागिदार थे एवं अब उस सत्ता पर पूर्णत: काबिज होना चाह रहे थे। यह आंदोलन मुख्यत: कुछ शहरी केंद्रों तक सीमित रहा और इसमें व्यापक जनभागीदारी लगभग नहीं के बराबर थी।

इस तरह प्रजामंडल आंदोलन का उल्लेख करके लेखक राजस्थान की आबादी के एक विशेष वर्ग को निरंकुश और दमनकारी सिद्ध करने का प्रयास करते हैं। मेरे विचार में यह एक कमजोर तर्क है, जो प्राथमिक ऐतिहासिक जांच भी नहीं झेल सकता।

लेखक पूर्वशाही परिवारों के लिए हिज हाईनेस जैसी उपाधियों के प्रयोग पर आपत्ति जताते हैं और तर्क देते हैं कि ऐसी संबोधन शैली मूलत: अपमानजनक है और बोलने वाले को संबोधित व्यक्ति से हीन दर्शाती है। लेकिन यह दावा एक समस्याग्रस्त मान्यता पर आधारित है–कि इन उपाधियों का प्रयोग थोपा गया है। वास्तव में किसी को इन्हें इस्तेमाल करने के लिए बाध्य करने वाली कोई दमनकारी व्यवस्था मौजूद ही नहीं है; इनका प्रयोग अनिवार्यता नहीं, बल्कि एक स्वैच्छिक चयन है।

राजसी उपाधियों का निरंतर प्रयोग राजनीतिक नहीं, बल्कि सांस्कृतिक और ऐतिहासिक परिघटना के रूप में बेहतर समझा जा सकता है। अनेक लोगों के लिए ये उपाधियाँ वंश, स्मृति और ऐतिहासिक निरंतरता के प्रतीक हैं, जो स्थानीय इतिहास और सामूहिक पहचान में रची–बसी हैं। इन्हें दासता भाव से नहीं, बल्कि उस विरासत की पहचान के रूप में प्रयोग किया जाता है, जिसे आधुनिक सामाजिक–राजनीतिक अभिजात वर्ग की अस्थायी सत्ता की तुलना में अधिक स्थिर माना जाता है।

एयर इंडिया के लोगो में महाराजा जैसे सांस्कृतिक प्रतीक इस बात को और स्पष्ट करते हैं। यह छवि किसी दासवत् दण्डवत होने का प्रतीक नहीं, बल्कि राजत्व की उस परंपरागत धारणा से जुड़ी है जिसमें संरक्षण, संरक्षणदाता–भाव और शासक तथा प्रजा के बीच पारस्परिक दायित्व पर बल दिया जाता था। लोकप्रिय कल्पना में इसका टिके रहना सामाजिक–राजनीतिक ऊंच–नीच का समर्थन नहीं अपितु सांस्कृतिक स्मृति की निरंतरता को दर्शाता है।

इसलिए पारंपरिक उपाधियों के प्रयोग को झूठी चेतना या आंतरिक दासता का प्रमाण नहीं समझना चाहिए। इसके बजाय यह अतीत से निरंतरता बनाए रखने का स्वैच्छिक प्रयास है, जिसके माध्यम से लोग आधुनिक राजनीतिक सत्ता की नैतिक और सांस्कृतिक उथलापन से असंतोष भी व्यक्त करते हैं।

राष्ट्रदूत के 20 जनवरी 2026 के अंक में प्रकाशित राजेन्द्र बोडा, अतिथि संपादक के संपादकीय पर प्रतिक्रिया प्राप्त हुई, जो अतिथि संपादक के रूप में प्रकाशित की जा रही है।

यह दृष्टिकोण सामंतवाद का महिमामंडन करने या उसकी असमानताओं को अनदेखा करने का आग्रह नहीं करता, बल्कि यह कहता है कि सामंत संस्थाओं को उनके ऐतिहासिक संदर्भ में समझा जाए

यह भी समझना आवश्यक है कि सामंत प्रतीक केवल पूर्वशाही परिवारों की उपाधियों तक सीमित नहीं हैं। वे राजस्थान की ऐतिहासिक पहचान और वैश्विक प्रस्तुति को आकार देने वाली भौतिक, सांस्कृतिक और संस्थागत विरासतों के व्यापक दायरे में फैले हुए हैं। उदाहरण के लिए राजस्थान के छह पहाड़ी किले, जो यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल हैं, केवल स्थापत्य अवशेष नहीं, बल्कि पूर्व–आधुनिक राजनीतिक संगठन, सैन्य रणनीति और सांस्कृतिक संरक्षण के स्थायी प्रतीक हैं।

इसी प्रकार जयपुर शहर, जिसे यूनेस्को ने प्रारंभिक आधुनिक शहरी नियोजन का उत्कृष्ट उदाहरण माना है, प्रत्यक्ष रूप से राजकीय पहल और शासकीय स्थापत्य दृष्टि से उत्पन्न हुआ। इसकी योजनाबद्ध ग्रिड संरचना, नागरिक स्थल और खगोलीय–प्रशासनिक सिद्धांतों का समन्वय इस धारणा को चुनौती देता है कि रियासती राज्य स्वभावत: जड़ और पिछड़े थे।

भाषायी और साहित्यिक परंपराएँ भी सामंतवाद की आलोचना को जटिल बनाती हैं। राजस्थानी भाषा और उसकी बोलियाँ दरबारी और प्रशासनिक संदर्भों में विकसित और मानकीकृत हुईं। डिंगल और पिंगल साहित्य, जिसे आधुनिक इतिहासलेखन में अक्सर उपेक्षित किया जाता है, वह राजकीय संरक्षण से समृद्ध हुआ और उत्तर भारतीय साहित्यिक परंपरा में योगदान दिया। इसी प्रकार राजस्थानी चित्रकला की प्रसिद्ध परंपराएँ भी अभिजात और राजकीय संरक्षण की देन हैं, जिन्हें आज विश्वभर के संग्रहालयों और अकादमिक जगत में सराहा जाता है।

यहाँ एक वैचारिक विरोधाभास उभरता है। जब राज्य और राष्ट्र स्वयं इन सांस्कृतिक प्रतीकों को धरोहर पर्यटन, राष्ट्रीय ब्रांडिंग और सॉफ्ट पावर के लिए उपयोग करते हैं, तब उन्हीं प्रतीकों को संरक्षित करने वाले सामंत वर्ग को नैतिक रूप से खारिज करना विश्लेषणात्मक रूप से असंगत प्रतीत होता है। यह दृष्टिकोण सामंतवाद का महिमामंडन करने या उसकी असमानताओं को अनदेखा करने का आग्रह नहीं करता, बल्कि यह कहता है कि सामंत संस्थाओं को उनके ऐतिहासिक संदर्भ में समझा जाए और उनकी सांस्कृतिक उपलब्धियों का मूल्यांकन उनकी सीमाओं के साथ किया जाए, न कि आधुनिक मापदंड से उन्हें एकरेखीय रूप से खारिज किया जाए।

लेखक लोकप्रिय संस्कृति में राजसी ठाठ–बाट के चित्रण से असहज महसूस करते हैं, लेकिन यह स्वीकार नहीं करते कि ऐसी प्रस्तुतियाँ आधुनिक पूंजीवादी बाजार की उपज हैं, न कि सामंती स्मृति की। क्या बिकता है, यह बाजार तय करता है, न कि भूतपूर्व राजपरिवार । यह प्रवृत्ति केवल भारत तक सीमित नहीं है। विश्वभर में ऐतिहासिक और राजसी ड्रामा लोकप्रिय हैं– डाउनटन एबे से द क्राउन तक और गेम ऑफ थ्रोन्स से द ट्ययूडर्स तक। उनका आकर्षण सत्ता समर्थन नहीं, बल्कि दृश्यात्मक भव्यता और कथा–निर्माण में है। विश्व भर में जापान, यूनाइटेड किंगडम, स्पेन, नॉर्वे, स्वीडन जैसे प्रगतिशील देशों में संवैधानिक राजतंत्र हैं। जबकि भारत में राजकीय उपाधियाँ केवल सांस्कृतिक हैं, क्योंकि राजाओं ने स्वेच्छा बदलते राजनैतिक परिवेश को देख भारत में राजनैतिक विलय करके अपनी राजनैतिक व्यवस्था को लोकतांत्रिक व्यवस्था में परिवर्तित करने में सहयोग किया। किन्तु क्या आधुनिक जोधपुर में गजसिंघजी या आधुनिक जयपुर में ब्रिगेडियर भवानी सिंघजी के योगदान को नकारा जा सकता है ? यह चिंता कि दर्शक राजसी सौंदर्यशास्त्र से मोहित हो जाएंगे, दर्शकों को कमतर बुद्धिमान मानने की पितृसत्तात्मक धारणा पर आधारित है, मानो वे इतिहास, कल्पना और राजनीतिक समर्थन में फर्क नहीं कर सकते।

लेख का मूल स्वर एक विशिष्ट वर्ग के प्रति वैचारिक शत्रुता से प्रेरित लगता है। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल द्वारा किसी व्यक्ति को पूर्वशासक कहने जैसी सामान्य सांस्कृतिक औपचारिकता को लेखक ने लगभग संवैधानिक संकट जैसा बना दिया जो वास्तव में पिज़्ज़ा पर विवादित टॉपिंग जितना ही गंभीर मुद्दा था। अंतत: यह लेख गंभीर वैचारिक व सांस्कृतिक आलोचना से अधिक वैचारिक अतिरेक का अभ्यास प्रतीत होता है, जहाँ ऐतिहासिक संदर्भों के सामान्य उल्लेख को सभ्यतागत पतन के संकेत के रूप में प्रस्तुत किया गया है। कथित खतरे और वास्तविक घटना के बीच असंगति इतनी स्पष्ट है कि यदि लेख से गंभीरता का आवरण हटा दिया जाए, तो यह ज़ेनोफोबिया से उपजी एक हास्यास्पद अतिशयोक्ति भर है ।

– अतिथि संपादक
एल के सिंह,
(डॉक्टर और सामाजिक टिप्पणीकार)

परीक्षा की शुचिता बनाम कक्षा की गुणवत्ता: डिजिटल निगरानी का असंतुलन और प्रस्तावित समाधान

प्रो.अशोक कुमार

भारतीय उच्च शिक्षा व्यवस्था आज एक अजीबोगरीब दौर से गुजर रही है। एक ओर हम डिजिटल इंडिया और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बातें करते हैं, वहीं दूसरी ओर हमारी पूरी प्रशासनिक मशीनरी आज भी इस बात पर केंद्रित है कि छात्र परीक्षा के तीन घंटों में नकल न कर पाए। विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में सीसीटीवी कैमरों का जाल बिछाया गया है, फ्लाइंग स्क्वायड तैनात किए जाते हैं और आधुनिक तकनीकों का प्रयोग केवल दंडात्मक उद्देश्यों के लिए किया जाता है। लेकिन प्रश्न यह है कि क्या केवल परीक्षा की निगरानी कर लेने से शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित हो जाएगी?

सच तो यह है कि परीक्षा की शुचिता की चिंता तब की जाती है जब कक्षा की गुणवत्ता दम तोड़ चुकी होती है। यदि छात्र को साल भर गुणवत्तापूर्ण शिक्षण नहीं मिला, तो वह परीक्षा में अनैतिक रास्तों की ओर मुड़ता ही है। यह लेख इस बात की वकालत करता है कि तकनीक का उपयोग केवल परीक्षा केंद्रों पर नहीं, बल्कि साल भर चलने वाली कक्षाओं में विकासात्मक रूप से किया जाना चाहिए।

दंडात्मक तकनीक बनाम विकासात्मक तकनीक

वर्तमान में हमारी शिक्षा व्यवस्था में तकनीक का उपयोग 'पुलिसिंग' जैसा है। हम छात्र को पकड़ने के लिए तकनीक पर भारी निवेश करते हैं, लेकिन उसे सिखाने के लिए नहीं। हम परीक्षा हॉल में उच्च क्षमता वाले कैमरे लगाते हैं, लेकिन उन्हीं कैमरों को कक्षा में लगाने से कतराते हैं जहाँ वास्तव में भविष्य गढ़ा जाता है।

यह उपचार पर ध्यान देने जैसी स्थिति है, जबकि आवश्यकता निवारण की है। यदि साल भर चलने वाली 1000 घंटों की कक्षाओं में गुणवत्तापूर्ण शिक्षण सुनिश्चित हो जाए, तो परीक्षा के उन 3 घंटों में किसी सीसीटीवी की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। तकनीक का असली लाभ तब है जब वह शिक्षण पद्धति को पारदर्शी और जवाबदेह बनाए।

स्मार्ट क्लासरूम ऑडिट सिस्टम: एक क्रांतिकारी समाधान

शिक्षा में व्याप्त विसंगतियों को दूर करने के लिए ''स्मार्ट क्लासरूम ऑडिट सिस्टम'' एक प्रभावी समाधान हो सकता है। इसके मुख्य बिंदु निम्नलिखित हैं:–

1. लाइव लर्निंग डैशबोर्ड

केवल रिकॉर्डिंग के बजाय, कक्षाओं को एक लाइव डैशबोर्ड से जोड़ा जाना चाहिए। इससे विश्वविद्यालय प्रशासन या उच्च शिक्षा निदेशालय वास्तविक समय में यह देख सकेगा कि किस कॉलेज में कौन सी कक्षा संचालित हो रही है। यह केवल निगरानी नहीं, बल्कि एक शैक्षिणक इन्वेंट्री होगी जो बताएगी कि संसाधनों का कितना उपयोग हो रहा है।

2. संसाधनों का इष्टतम उपयोग और प्रशासनिक जिम्मेदारी

सरकारें करोड़ों रुपये खर्च करके कॉलेजों में स्मार्ट बोर्ड, प्रोजेक्टर और लैब स्थापित करती हैं। अक्सर देखा गया है कि ये संसाधन धूल फांकते रहते हैं या केवल निरीक्षण के दिन ही बाहर निकलते हैं। डिजिटल ऑडिट के माध्यम से यह सुनिश्चित किया जा सकेगा कि सरकारी धन का उपयोग वास्तव में छात्रों के हित में हो रहा है।

3. शैक्षणिक जवाबदेही और उपस्थिति

अक्सर दूर–दराज के क्षेत्रों में शिक्षकों की अनुपस्थिति एक बड़ी समस्या है। डिजिटल निगरानी शिक्षकों को उनकी उपस्थिति और शिक्षण के प्रति जवाबदेह बनाएगी। जब शिक्षक को पता होगा कि उसकी कक्षा का ऑडिट किया जा सकता है, तो शिक्षण की गुणवत्ता और गंभीरता में स्वत: ही सुधार होगा।

डिग्री वितरण बनाम ज्ञानार्जन

वर्तमान में बिना पढ़ाई के डिग्री बांटने की जो प्रथा चल पड़ी है, उसने भारतीय युवाओं की वैश्विक साख को खतरे में डाल दिया है। जब कक्षाएं नियमित नहीं होतीं, तो छात्र केवल पास होने के लिए रट्टा मारते हैं या नकल का सहारा लेते हैं। इस प्रक्रिया में डिग्री तो मिल जाती है, लेकिन योग्यतानगण्य रह जाती है। कक्षा की डिजिटल निगरानी इस डिग्री मिल संस्कृति पर प्रभावी लगाम लगाएगी।

कार्यान्वयन के व्यावहारिक चरण

इस व्यवस्था को धरातल पर उतारने के लिए एक व्यवस्थित दृष्टिकोण की आवश्यकता है:–

क. सेंट्रल मॉनिटरिंग सेल की स्थापना: प्रत्येक विश्वविद्यालय में एक समर्पित मॉनिटरिंग सेल होना चाहिए। यह सेल रैंडम आधार पर विभिन्न कक्षाओं का लाइव ऑडिट करे। इसका उद्देश्य शिक्षकों को प्रताड़ित करना नहीं, बल्कि शैक्षणिक बाधाओं की पहचान करना होना चाहिए।

ख. फीडबैक लूप और श्रेष्ठता का सम्मान: कैमरों का उपयोग दंडात्मक न होकर एप्रिसिएशन के लिए भी होना चाहिए। बेहतरीन शिक्षण करने वाले शिक्षकों के लेक्चर को रिकॉर्ड करके अन्य कॉलेजों के साथ साझा किया जाना चाहिए। इससे एक नॉलेज बैंक तैयार होगा जिसका लाभ उन छात्रों को भी मिलेगा जिनके पास अच्छे शिक्षकों का अभाव है।

ग. डेटा गोपनीयता और सुरक्षा:यह सुनिश्चित करना अनिवार्य है कि फुटेज का उपयोग केवल और केवल शैक्षणिक सुधार के लिए हो। डेटा का किसी भी प्रकार का दुरुपयोग रोकने के लिए कड़े कानूनी और तकनीकी सुरक्षा कवच होने चाहिए।

सुरक्षा और अनुशासन का अतिरिक्त लाभ

कक्षाओं में डिजिटल निगरानी का एक और बड़ा पहलू सुरक्षा है। यह परिसर में अनुशासन बनाए रखने और रैगिंग जैसी घटनाओं को रोकने में रामबाण सिद्ध हो सकता है। छात्र और छात्राएं परिसर में सुरक्षित महसूस करेंगे, जिससे शैक्षणिक वातावरण और अधिक सकारात्मक होगा।

चुनौतियां और विरोध के स्वर

निश्चित रूप से, इस तरह के प्रस्ताव का विरोध निजता और अकादमिक स्वतंत्रता के नाम पर होगा। लेकिन यहाँ यह तर्क महत्वपूर्ण है कि एक सार्वजनिक शिक्षक का कक्षा में शिक्षण निजी कृत्य नहीं, बल्कि लोक कर्तव्य है। जब हम मेट्रो, रेलवे स्टेशन और सड़कों पर सुरक्षा के लिए कैमरों को स्वीकार करते हैं, तो राष्ट्र निर्माण के सबसे महत्वपूर्ण स्थल कक्षा में पारदर्शिता से क्यों डरते हैं?

निष्कर्ष: एक नई दिशा की ओर

''परीक्षा की पवित्रता तब तक अधूरी है, जब तक कक्षा की निरंतरता और गुणवत्ता सुनिश्चित न हो।'' यदि हम परीक्षा के 3 घंटों को कैमरे की जद में रख सकते हैं, तो साल भर चलने वाली 1000 घंटों की कक्षाओं को क्यों नहीं?

डिजिटल निगरानी का असंतुलन दूर करना आज के समय की सबसे बड़ी मांग है। हमें तकनीक को केवल चेक पोस्ट की तरह नहीं, बल्कि प्रकाश स्तंभ की तरह उपयोग करना होगा। जब हमारी कक्षाएं पारदर्शी, जवाबदेह और गुणवत्तापूर्ण होंगी, तभी हम सही मायने में एक ज्ञान आधारित समाज का निर्माण कर पाएंगे। स्मार्ट क्लासरूम ऑडिट केवल एक प्रशासनिक कदम नहीं, बल्कि भारतीय शिक्षा व्यवस्था के कायाकल्प की एक अनिवार्य आवश्यकता है।

–प्रो. अशोक कुमार,
पूर्व कुलपति कानपुर, गोरखपुर विश्वविद्यालय, विभागाध्यक्ष राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर

डिजिटल राजस्थान में बढ़ता अकेलापन

भूपेश दीक्षित

राजस्थान आज डिजिटल क्रांति के दौर में तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण की रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश में 5 करोड़ से अधिक लोग इंटरनेट का उपयोग कर रहे हैं। 'पॉपुलेशन प्रोजेक्शन फॉर इंडिया एंड स्टेट्स' रिपोर्ट बताती है कि वर्ष 2026 तक राजस्थान में 10 से 29 वर्ष आयु वर्ग की आबादी लगभग 3 करोड़ होगी। यह वह पीढ़ी है जिसके हाथों में प्रदेश का आर्थिक, सामाजिक और तकनीकी भविष्य होगा। लेकिन डिजिटल प्रगति के इस उजले पहलू के साथ एक गंभीर चुनौती भी तेजी से उभर रही है। आज के युवा अपना अधिकांश समय स्मार्टफोन, सोशल मीडिया, ऑनलाइन गेमिंग और स्क्रॉलिंग में बिता रहे हैं। इसका सीधा असर उनकी नींद, एकाग्रता, पढ़ाई, कार्यक्षमता और शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ रहा है। डिजिटल कंटेंट कंपनियाँ ऐसे अल्गोरिथम बना रही हैं जो बच्चों और युवाओं को घंटों स्क्रीन से बांधे रखते हैं। समस्या तकनीक के उपयोग की नहीं बल्कि उसके अनियंत्रित और व्यसनी स्वरूप की है। ऑनलाइन शॉपिंग, रील्स, लाइक्स, कमेंट्स और स्टेटस अपडेट जैसी गतिविधियों ने युवाओं को आभासी दुनिया में तो जोड़ दिया है लेकिन वास्तविक समाज से दूर कर दिया है। परिणामस्वरूप अकेलापन, तनाव, अवसाद, भावनात्मक अस्थिरता और आत्महत्या के विचार तेजी से बढ़ रहे है। मानसिक स्वास्थ्य संकट अब केवल व्यक्तिगत समस्या नहीं रह गया बल्कि एक गंभीर सार्वजनिक स्वास्थ्य चुनौती बन चुका है। राजस्थान राज्य अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार वर्ष 2024 में प्रदेश में 5530 लोगों की मृत्यु आत्महत्या के कारण हुई यानी औसतन हर दिन लगभग 15 परिवार इस दर्द से गुजर रहे है। ये आंकड़े केवल संख्याएँ नहीं बल्कि टूटते सामाजिक ताने–बाने की चेतावनी हैं।

इसी पृष्ठभूमि में आर्थिक सर्वेक्षण 2025–26 एक बेहद महत्वपूर्ण संदेश देता है। सर्वेक्षण बताता है कि जिन राज्यों और उनके जिलों में जहाँ सामाजिक जुड़ाव मजबूत है जैसे– बिहार और उत्तरप्रदेश, वहाँ आत्महत्या की दर कम है। वहीं जिन राज्यों में लोग परिवार और समुदाय से भावनात्मक रूप से दूर होते जा रहे हैं जैसे– केरल और तमिलनाडु, वहाँ आत्महत्या दर अधिक है। इसका स्पष्ट अर्थ है कि डिजिटल कनेक्टिविटी मानवीय रिश्तों का विकल्प नहीं बन सकती।

राजस्थान के कोटा, सीकर और जयपुर जैसे शैक्षणिक केंद्रों में लाखों विद्यार्थी घर से दूर रहकर पढ़ते हैं। उनके पास ऑनलाइन संपर्क तो है लेकिन भावनात्मक सहारे का अभाव है जो अक्सर गहरे मानसिक तनाव को जन्म देता है और जिसके दुष्परिणाम हमें आत्महत्या के रूप में हमें देखने को मिल रहे है। स्क्रीन पर मिलने वाली क्षणिक सराहना वास्तविक अपनत्व का स्थान नहीं ले सकती। इस चुनौती से निपटने के लिए केवल काउंसलिंग अथवा हेल्पलाइन पर्याप्त नहीं हैं। जरूरत है व्यापक सामाजिक और शैक्षणिक हस्तक्षेप की जैसे स्कूलों में मेंटल एंड डिजिटल वेलनेस कार्यक्रम, मेंटरशिप प्रणाली, बड्डी सिस्टम, सहपाठी सहयोग समूह, खेल–कला गतिविधियाँ और परिवारों में खुला संवाद।

समस्या के समाधान हेतु आगामी राज्य बजट में तीन ठोस प्रमाण आधारित कदम उठाए जा सकते हैं। पहला, जिला मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम का विस्तार, स्कूल–कॉलेज आधारित काउंसलिंग सेवाओं और सामुदायिक आउटरीच कार्यक्रमों के लिए वित्तीय प्रावधान। दूसरा, मेंटल हेल्थ एंड डिजिटल वेलनेस मिशन के तहत शिक्षक प्रशिक्षण और अभिभावक जागरूकता अभियान और तीसरा, युवा साथी केंद्रों और नेहरू युवा केंद्रों को मजबूत कर सामुदायिक संवाद और परामर्श की सुविधाओं में विस्तार।

राजस्थान के पास टेली–मानस, जिला मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम, स्कूल हेल्थ प्रोग्राम और युवा साथ केंद्र जैसी व्यवस्थाएँ पहले से मौजूद हैं। आवश्यकता बस इतनी है कि नीति और बजट दोनों के केंद्र में सामाजिक जुड़ाव को प्राथमिकता दी जाए। क्योंकि जीवन बचाने का सबसे बड़ा सहारा दवाइयाँ, मोबाइल, इन्टरनेट या डिजिटल कनेक्टिविटी नहीं बल्कि मजबूत रिश्ते, सच्ची बातचीत और संवेदनशील समाज हैं। सरकार द्वारा जनहित में उठाये जाने वाले इन्ही ठोस क़दमों से आयुष्मान स्वस्थ राजस्थान और विकसित राजस्थान 2047 का सपना साकार होगा।

–भूपेश दीक्षित,
जनस्वास्थ्य विशेषज्ञ एवं संयोजक, द राजस्थान मेंटल हेल्थ एंड सुसाइड प्रिवेंशन नेटवर्क, जयपुर (राजस्थान)

खेजड़ी बचाओ आंदोलन – अनशन पर बैठे संत की तबीयत बिगड़ी

- **लोगों ने खुद को रेलिंग से बांधा; संत बोले-कानून नहीं बना तो हालत खराब कर देंगे**
- **अनिश्चितकालीन अनशन तीसरे दिन बुधवार को भी जारी रहा**

बीकानेर। खेजड़ी बचाने के लिए चल रहे आंदोलन में अनिश्चितकालीन अनशन तीसरे दिन बुधवार को भी जारी रहा। बिश्नोई धर्मशाला के सामने पब्लिक पार्क में 450 से ज्यादा पर्यावरण प्रेमी, संत और 50 महिलाएं आंदोलन में डटी हुई हैं। कुछ आंदोलनकारी खुद को लोहे की रेलिंग से बांधकर प्रदर्शन कर रहे हैं। अनशन पर बैठे धवा डोली मठ के महंत संत लाल दास की तबीयत ज्यादा खराब हो गई है। उन्हें पीबीएम हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया है।

सच्चिदानंद महाराज के नेतृत्व में बड़ी संख्या संत अनशन पर बैठे हैं। उन्होंने कहा कि खुद को सनातनी कहने वाली सरकार निष्ठुर बनी हुई है। अन्न–जल त्यागकर बैठे लोगों की तबीयत बिगड़ रही है। कानून नहीं बना तो हालत खराब कर देंगे। बस तारीख बता दो, आमरण अनशन खत्म कर चले जाएंगे।

अनशन के दौरान पर्यावरण प्रेमी महेंद्रकुमार आंखों पर पट्टी बांधकर बैठे हैं। उन्होंने निर्णय होने तक पट्टी न खोलने की बात कही है। आंदोलन के नेतृत्वकर्ताओं ने स्पष्ट किया है कि मांगों पर ठोस फैसला होने तक अनशन शांतिपूर्ण तरीके से जारी रहेगा। कलेक्ट्रेट और बिश्नोई धर्मशाला के बाहर पुलिस के करीब डेढ़ हजार जवान कड़ी निगरानी कर रहे हैं। वहीं, बिश्नोई धर्मशाला में 100 बेड का अस्थायी अस्पताल बनाया गया है।

तबीयत बिगड़ने पर अनशनकारी मांगीलाल नोखड़ा को एम्बुलेंस से पीबीएम हॉस्पिटल ले जाते लोग। बीकानेर में कलेक्ट्रेट ऑफिस के बाहर भारी मात्रा में पुलिस बल तैनात है। अन्न–जल छोड़ने से अनशनकारियों की लगातार तबीयत बिगड़ रही है। मेडिकल टीम मौके पर ही हेल्थ चेकअप कर रही है। बीकानेर में कलेक्ट्रेट ऑफिस के बाहर भारी मात्रा में पुलिस बल तैनात किया गया है। संतों की तबीयत बिगड़ने के बाद प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता कर दिया है। एडिशनल एसपी (सिटी) चक्रवर्ती सिंह और एडिशनल एसपी(ग्रामीण) बनवारी लाल दोनों ही अनशन स्थल के आसपास ही तैनात हैं। एसपी कावेंद्र सिंह सागर का कहना है कि स्थिति को देखते हुए कलेक्ट्रेट और धरना स्थल पर करीब डेढ़ हजार जवानों की तैनाती की गई है।

आंदोलन से जुड़े विक्रम बिश्नोई ने बताया कि धरना स्थल पर 24 घंटे से अधिक समय से अनशनकारियों ने पानी तक नहीं पीया है। कई अनशनकारियों की उम्र 70 साल से अधिक है, ऐसे में उनकी तबीयत भी नाजुक हो गई है। संत लाल दास महाराज भी डि–हाइड्रेट होकर बेहोश हो गए थे। उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती किया गया है। उनका सीटी स्कैन किया जाएगा। हमें विश्वास है कि किसी के साथ कुछ गंभीर नहीं हो। धरना स्थल पर अनशनकारी मांगीलाल नोखड़ा की भी तबीयत बिगड़ गई है। उनका बीपी 300 तक पहुंच गया है। उन्हें भी एम्बुलेंस से पीबीएम हॉस्पिटल शिफ्ट किया जा रहा है। अनशनकारियों की संख्या को देखते हुए बिश्नोई धर्मशाला में ही एक अस्थायी अस्पताल बनाया गया है। चिकित्सा विभाग के संयुक्त निदेशक देवेंद्र चौधरी ने बताया– 100 बेड का हॉस्पिटल यहां तैयार किया जा रहा है। अब तक 50 से ज्यादा बेड लग चुके हैं। सीएमएचओ डॉ. पुखराज साध का कहना है कि सभी मरीजों को चेक किया जा रहा है। जिनकी जरा भी तबीयत कमजोर लग रही है, उन्हें भर्ती किया जा रहा हैं।

फलोदी जिले से आए श्यामलाल का कहना है कि मैंने जिला कलेक्टर के माध्यम से राष्ट्रपति को पत्र भेजा है। पत्र में लिखा है कि मेरे समाज के संत आमरण अनशन पर बैठे हैं। यह मुझसे देखा नहीं जाता है। मैं राष्ट्रपति से कहना चाहता हूं कि या तो वे संत–महात्माओं का आमरण अनशन खत्म करवाएं या फिर मुझे इच्छा मृत्यु की अनुमति दें। सरकार हमारे धैर्य की परीक्षा न ले। श्रीगंगानगर किसान संघर्ष समिति के जिलाध्यक्ष अमर सिंह बिश्नोई ने कहा कि गूंगी–बहरी सरकार को जगाने के लिए उन्हें यह प्रदर्शन करना पड़ रहा है। प्रधानमंत्री दुनिया भर में घूमकर ग्लोबल वार्मिंग का संदेश दे रहे हैं। जब दुनिया को पर्यावरण के महत्व की जानकारी भी नहीं थी, तब यहां के लोगों ने पेड़ों की रक्षा के लिए अपने बलिदान दिए थे।

प्रशासन किसी स्थिति से निपटने के लिए अलर्ट मोड है। अनशन पर बैठे लोगों की तबीयत लगातार बिगड़ रही है। मेडिकल टीम मौके पर ही स्वास्थ्य जांच कर रही है।

राशिफल

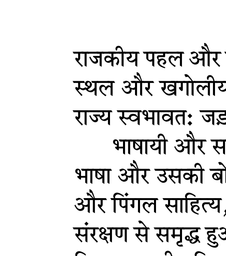

पंडित अनिल शर्मा

गुरूवार 5 फरवरी, 2026

फाल्गुन मास, कृष्ण पक्ष, चतुर्थी तिथि, गुरूवार, विक्रम संवत 2082, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र रात्रि 10:57 तक, सुकर्मा योग रात्रि 12:04 तक, बव करण दिन 12:16 तक, चन्द्रमा कन्या राशि में संचार करेगा।

गृह स्थिति: सूर्य–मकर, चन्द्रमा–कन्या, मंगल–मकर, बुध–कुम्भ, गुरू–मिथुन, शुक्र–मकर, शनि–मीन, राहु–कुम्भ, केतु–सिंह

आज शुक्र कुम्भ राशि में रात्रि 1:11 पर प्रवेश करेगा। आज चतुर्थी व्रत है। चन्द्रोदय जयपुर में रात्रि 9:41 पर होगा।

श्रेष्ठ चौघड़िया: शुभ सूर्योदय से 8:36 तक, चर 11:19 से 12:41 तक, लाभ–अमृत 12:41 से 3:24 तक, शुभ 4:46 से सूर्यास्त तक।

राहूकाल: 1:30 से 3:00 तक। सूर्योदय 7:14, सूर्यास्त 6:07

मेष
स्वास्थ्य में सुधार होगा। विवादित मामलों से राहत मिल सकती है। अस्त–व्यस्त दिनचर्या में सुधार होगा। अनहोनी की आशंका से बना हुआ मन का भय दूर होगा।

वृष
व्यावसायिक कार्यों पर ध्यान देना ठीक रहेगा। चलते कार्यों में प्रगति होगी। व्यावसायिक आय में वृद्धि होगी। संभावित स्त्रोत से धन प्राप्त होगा।

मिथुन
घर–परिवार में अतिथियों का आगमन बना रहेगा। परिवार में उत्सव जैसा माहौल रहेगा। धार्मिक–सामाजिक समारोह सम्पन्न हो सकते हैं।

कर्क
व्यावसायिक संपर्क बनेंगे। व्यावसायिक वार्ता सफल रहेगी। व्यावसायिक अनुबंध प्राप्त होंगे। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी। परिवार में मन को प्रसन्न करने वाले संदेश प्राप्त होंगे।

सिंह
आर्थिक मामलों में संतुलन बना रहेगा। व्यावसायिक कार्यों के संबंध में शुभ संदेश प्राप्त होंगे। अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। घर–परिवार में चल रहे आपसी मतभेद दूर होंगे।

कन्या
आर्थिक/वित्तीय मामलों के लिए दिन अच्छा रहेगा। आय में वृद्धि होगी। व्यावसायिक कार्यों में आज उचित सफलता मिलेगी। अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। स्वास्थ्य ठीक रहेगा।

तुला
व्यावसायिक कार्यों के कारण भागदौड़ रहेगी। व्यावसायिक खर्चों में वृद्धि हो सकती है। आर्थिक मामलों में परेशानी हो सकती है। मन में असंतोष बना रहेगा।

वृश्चिक
आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी। आय में वृद्धि होगी। व्यावसायिक वार्ता के लिए दिन अच्छा रहेगा। व्यावसायिक प्रयासों में उचित सफलता मिलेगी।

धनु
व्यावसायिक कार्यों को प्राथमिकता से करने का प्रयास करें। अटके हुए कार्य शीघ्रता/सुगमता से बनने लगेंगे। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी। परिवार में उत्सव जैसा माहौल रहेगा।

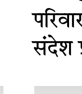

मकर
नवीन कार्यों के संबंध में शुभ संदेश प्राप्त होंगे। अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। धार्मिक स्थान की यात्रा संभव है। व्यावसायिक/आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

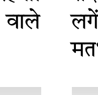

कुंभ
चन्द्रमा अष्टम भाव में शुभ नहीं है। शुभ कार्यों में व्यवधान हो सकता है। आज आवश्यक कार्यों में विलम्ब हो सकता है। बनते कार्य बिगड़ सकते हैं। व्यावसायिक/पारिवारिक खर्चों में वृद्धि हो सकती है।

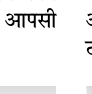

मीन
परिवार में आपसी सहयोग–समन्वय बना रहेगा। परिवार में उत्सव जैसा माहौल रहेगा। परिवार में शुभ–मांगलिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं।